

सम्पादकीय

बच्चों के लिए टीका

पहली बार इस टीके के जरिए 2 साल की उम्र तक के बच्चों को कवर करने की सोची जा रही है। इससे न केवल तीसरी लहर में बच्चों के मुख्य निशाना होने संबंधी चिंता को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि स्कूलों की पढाई को सामान्य बनाना भी आसान होगा। देश में 2 से 18 साल उम्र तक के बच्चों के लिए कोरैक्सीन टीका इस्तेमाल करने को लेकर एक्सपर्ट कमिटी की सिफारिश ऐसे समय आई है जब कोरोना संक्रमण निचले स्तर पर है, जनजीवन सामान्य होने की ओर है और अर्थव्यवस्था भी झटकों से उबर रही है। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी सच है कि टीकाकरण अभियान बीच-बीच में रेकॉर्ड बनाने के बावजूद अपेक्षा के अनुरूप रफतार हासिल नहीं कर सका है (19.8 फीसदी आबादी ही टीके के दोनों ढोज ले सकी है) और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी समाप्त नहीं की जा सकी है। हालांकि इस टीके को अभी डीसीजीआई (इंग्रेस कंट्रोलर जेनरल ऑफ इंडिया) की मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन सज्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी (एसईसी) की सिफारिश के रूप में एक अहम पड़ाव पार कर लेने के बाद इस टीके से होने वाले नफा-नकसानों की चर्चा होने लगी है। सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसके तीसरे फेज के फ्रिनिकल ट्रायल डेटा को लेकर सवाल बने हुए हैं। कोरैक्सीन को सुरक्षित वैक्सीन के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता पर भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। डब्ल्यूयूचओ इसे टीकों की अपनी आधिकारिक सूची में शामिल करेगा या नहीं इस पर फैसला अभी नहीं हुआ है। बहरहाल, अपने देश में तो यह टीका न केवल बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है बल्कि अब तक के अनुभवों पर खरा भी उतरा है।

फिर भी डब्बूयूएचओ की मान्यता में देरी का असर इस रूप में जरूर देखने का मिल सकता है कि सरकार की मंजूरी मिल जाने और टीकाकरण अभियान में शामिल कर लिए जाने के बाद भी इसे लेने में लोग शुरू में कुछ हिचक दिखाएं। मगर हर टीके को लेकर शुरू में ऐसी हिचक देखी जाती रही है जो समय के साथ दूर होती है। इससे पहले अगस्त में जायडस कैडिला के कोरोना टीके को भी आपात कालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी, लेकिन वह 12 से 18 साल के बच्चों के लिए था।

पहली बार इस टीके के जरिए 2 साल की उम्र तक के बच्चों को कवर करने की सोची जा रही है। इससे न केवल तीसरी लहर में बच्चों के मुख्य निशाना होने संबंधी चिंता को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि स्कूलों की पढ़ाई को सामान्य बनाना भी आसान होगा। स्कूल खुलने के बावजूद ऑफलाइन पढ़ाई अभी कई तरह की बंदिशों के बीच ही चल रही है। हाल में आए आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जरूरी उपकरणों तक पहुंच नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई से स्ट्रॉटेजेस की समझ में होने वाले इजाफे को लेकर कई तरह के सवाल हैं। निश्चित रूप से टीके की सुरक्षा और उसकी कारगरता को लेकर सारे संदेह पहले दूर कर लिए जाएं, लेकिन उसके बाद बच्चों को टीकाकरण के दायरे में जल्द से जल्द लाना सबके हित में होगा।

कितने बहुकोणीय होंगे आगामी चुनाव

नरेंद्र नाथ

अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में विपक्षी एकता की कोशिश फिलहाल धूमिल हो चुकी है। सभी सियासी दल बहुकोणीय चुनाव के नफा-नुकसान की चर्चा करने लगे हैं। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब तक के जो राजनीतिक संकेत हैं उसके अनुसार इन सभी राज्यों में बहुकोणीय चुनाव ही होंगे। हाल के सालों में आम धारणा यही बनी है कि बहुकोणीय चुनाव से बीजेपी को लाभ होता है क्योंकि इससे उनके विरोधी मतों का ही बंटवारा होता है। हालांकि जानकारों के अनुसार हर चुनाव के समीकरण अलग होते हैं, और इसे कोई एक स्थापित ट्रैंड मान लेना मुनासिब नहीं। लेकिन पांच राज्यों के चुनाव में आए नतीजे एक ठोस ट्रैंड बता सकते हैं। अभी बहुकोणीय चुनाव और इसके असर की बात पर बहस इसलिए शुरू हुई कि एक के बाद एक कई घटनाक्रम हुए हैं। पिछले हफ्ते गुजरात में हुए निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भले सीट जीतने में सफल नहीं रही, लेकिन कांग्रेस के वोट बैंक में उसने बड़ी सेंध लगाई। इसका असर यह हुआ कि बीजेपी पिछली बार से भी बड़ी जीत पाने में सफल रही। गुजरात में भी अगले साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लखीमपुर कांड के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश में आक्रामक हुई और ताराणसी में बड़ी रैली कर उन्होंने कांग्रेस के चुनावी प्रचार का शंखनाद किया, उसके बाद रहां भी यह बात उठी कि अगर कांग्रेस अपना वोट बढ़ाती है तो वह किसकी कीमत पर बढ़ाएगी। तर्क दिया गया कि जितना कांग्रेस बहेतर करेगी, बीजेपी के लिए राहत की बात होगी क्योंकि इससे बीजेपी विरोधी

तेल की तरह बढ़े बिजली का दाम

भरत झुनझुनवाला

वर्तमान बिजली संकट का तात्कालिक कारण कोयले की शॉर्टेज है लेकिन यह शॉर्टेज खुद ग्रूबल वार्मिंग की वजह से है। आगे बढ़ने से पहले कुछ कथित कारणों का निवारण जरूरी है। पहला कथित कारण है कि कोविड संकट के बाद अर्थव्यवस्थाएं फिर स्पीड पकड़ रही हैं जिससे बिजली की मांग बढ़ी और संकट पैदा हो गया है। यह मान्य नहीं है क्योंकि अपने देश में जितना कोयले का उत्पादन अप्रैल से सितंबर 2019 में हुआ था, उससे 11 प्रतिशत अधिक उत्पादन अप्रैल से सितंबर 2021 में हुआ है। कोविड के बाद कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ा है इसलिए यह संकट का कारण नहीं है। दूसरा कथित कारण यह बताया जा रहा है कि चीन ने ॲस्ट्रेलिया से कोयले के आयात पर रोक लगा दी है। यह भी मान्य नहीं है, क्योंकि ॲस्ट्रेलिया के कोयले की मांग बढ़ी हुई है।

चीन के कोयला न खरीदने से विश्व बाजार में ॲस्ट्रेलिया के कोयले

चान क कायला न खारदन से विश्व बाजार म आस्ट्रोलया क कायल की सुपुर्झ में कमी नहीं आई है। तीसरा कथित कारण है कि थर्मल पावर की जगह पर सोलर और विंड पावर के बढ़ते उपयोग के चलते कोयले के उत्पादन से उद्यमियों का ध्यान हट गया है और संकट पैदा हुआ है। यह तर्क भी सटीक नहीं बैठता है। अगर यह कारण होता तो कोयले की मांग कम होती, कोयले की उपब्युता बढ़ती और उसके दाम गिरते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए तीनों कारण स्वीकार नहीं हैं।

चीनी मंसूबे नाकाम करने पर अड़ा भारत, किस तरह सत्ता में आने के बाद से शी चिनफिंग कर रहे नाजायज विस्तार

रंजीत कुमार

पूर्वी लद्दाख की सीमांत बर्फली चोटियों पर गत डेढ़ वर्षों से डेरा जमाए थे औं चीनी सैनिकों को वापस पुरानी स्थिति पर लौटने के लिए राजी करने में इस बार भी कामयाबी नहीं मिली। अपने विदेश मंत्री के भारत को भरोसा दिलाने वाले दुश्सांखे में दिए गए बयानों के विपरीत चीन ने 10 अक्टूबर को हुई 13वें दौर की सैन्य कमांडर वार्ता के दौरान अडियल रुख अपनाया और कहा कि भारत गैरवजिब और अनुचित मांग कर रहा है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पिछले साल पांच मई को पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों (गलवान, पैगोंग झील, गोगरा, हॉट स्ट्रिंग) और उसके पहले देपसांग के इलाकों में की गई सैन्य घुसपैठ को खत्म करने के लिए चीन ने भारत से गहन सौदेबाजी की है।

लेकिन भारत ने दृढ़तापूर्वक कह दिया है कि 5 मई से पहले की यथास्थिति बहाल करने पर ही बात बनेगी। गलवान, पैगोंग झील के इलाके में तो चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वापस लौटने की सहमतियों का पालन कर चुके हैं। लेकिन इसमें भी चीन का पलड़ा इस मायने में भारी रहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय इलाकों में बफर जोन बनाया गया है, जहां भारतीय सेना गश्त नहीं कर सकती। यह भारतीय सेना की जीत इस मायने में कही जा सकती है कि आखिर चीनी सेना उन इलाकों में दोनों को मान्य वास्तविक नियंत्रण रेखा के अनुरूप पीछे हटने को मजबूर हुई है। लेकिन चीन दो कदम आगे बढ़कर एक कदम पीछे हटने की रणनीति पर चल रहा है। इसके अनुरूप चीनी राजनेता ओ? आल राजनयिक बार-बार कह रहे हैं कि भारत और चीन बीच रास्ते में मिल कर कोई समाधान खोजें। आधे रास्ते पर मिलकर मसले का हल खोजने के चीनी प्रस्ताव का मतलब यही है कि वह जिन भारतीय इलाकों में बढ़ चुका है वहां से आधा रास्ता पीछे लौटने पर

विचार हो। भारत यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो भारतीय इलाके का एक हिस्सा चीन के पास ही रह जाएगा। इसलिए भारत देश रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सेना प्रमुख सबने साफ कर दिया है कि इस मसले पर चीन का सवाल ही नहीं उठता। चीन को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि चीनी घुसपैठ को निरस्त करने के लिए भारत अनंत काल तक डटे रहते हुए मुस्तेदी से अपने इलाके पर दावा जताता रहेगा।

इस बीच भारतीय सेना के लिए सैन्य तैनाती को असहनीय बनाने के इरादे से चीन पूर्वी लद्धाख के सीमांत इलाकों में अपने सैनिकों के रहने सहने और उनके हथियार रखने के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाता जा रहा है। 10 अक्टूबर को दोनों सेनाओं के कमांडरों की 13वें दोर की बातचीत करीब दो महीने बाद हो रही थी। लेकिन इसके पहले पिछले एक महीने में चीन ने उत्तराखण्ड के बाराहुती और अरुणाचल प्रदेश देशी सीमांत इलाकों में अपने सैनिकों से अतिक्रमण करवा कर यह संदेश दिया कि वह न केवल पश्चिमी सेक्टर के पूर्वी लद्धाख, बल्कि मध्य सेक्टर के बाराहुती और पूर्वी सेक्टर के अरुणाचल प्रदेश को भी मौजूदा विवादों के धेरे में शामिल कराना चाहता है। चीन इसके पहले यह संदेश दे चुका है कि 1959 में चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने सीमा मसले का जिस वास्तविक नियंत्रण रेखा के अनुरूप हल करने का प्रस्ताव रखा था तो भारत उसे मान ले। उस प्रस्ताव में अक्साई चिन को चीन के शिनजियांग प्रदेश के तहत शामिल करते हुए प्रस्ताव किया गया था कि दोनों सेनाओं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लगाने वाली मैकमेहोन रेखा (जिसे चीन अद्वैत बताता रहा है) से 20-20 किलोमीटर पीछे हट जाएं, जबकि लद्धाख और अक्साई चिन वाले इलाकों में जो देश जहां तक मौजूद है वहां तक अपने इलाका मान ले। यह प्रस्ताव करने के पहले चीन लद्धाख के इलाके में काफी आगे बढ़ चुका था। भारत ने 1959 में भी इस प्रस्ताव को नामंजूहा कर दिया था। अनधिकृत तौर पर कुछ महीनों पहले दोहराए गए इस प्रस्ताव पर भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा एतराज किया, क्योंकि

भारत और चीन के बीच 1993, 1996, 2005 और 2013 में परस्पर विश्वास निर्माण की जो संधियां हुई, उनमें तत्कालीन अधिकार वाले इलाकों के अनुरूप ही वास्तविक नियन्त्रण रेखा का ज़िक्र किया गया और 1959 के चांगो प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच 13वें दौर की जो बातचीत चली है वह इन चारों समझौतों के अनुरूप ही है। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच जो संवाद हुए हैं वे भी इनके अनुरूप हैं।

बहरहाल, चीन के अडीयिल रुख के मद्देनजर ऐसा लगता है कि 2020 की बर्फली सदियों की तरह 2021 की सदियों में भी भारतीय सेना को वहीं तैनात रहना होगा। हालांकि वित्तीय संकट में चल रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वी लद्धाख के सीमांत इलाकों की बर्फली चौटियों पर 50 हजार से अधिक सैनिकों को तैनात रखने पर रोजाना ४४८००० रुपये का खर्च भारी साबित हो रहा है। लेकिन राष्ट्रपति शी चिन फिंग की विस्तार की नाजायज महत्वाकांक्षाओं का डटकर मुकाबला अगर आज नहीं किया तो 2047 तक चीन को दुनिया का नंबर एक ताकतवर और विकसित देश बनाने के उनके सपनों को पर लगा जाएंगे। वास्तव में 2013 में सत्ता संभालने के बाद से ही राष्ट्रपति शी ने दक्षिण चीन सागर सहित भारत के सीमांत इलाकों पर सामरिक व सैन्य दबाव बढ़ाकर अपने विस्तारवादी सपनों को पूरा करने की नीति लागू की है। इसके तहत चीनी सेना ने 2017 में डोकलाम सहित कुल पांच बार भारतीय इलाकों में सैन्य घुसपैठ की है। हर बार भारतीय पक्ष ने अपने इलाके को खाली कराने में कामयाबी हासिल कर ली। इस बार राष्ट्रपति शी यह सदेश नहीं देना चाहते कि चीनी सेना भारतीय दबाव में पीछे हटी है। लेकिन भारत के जांबाज सैनिक पिछले साल 15 जून के गलवान हमले से प्रेरणा लेते हुए इस बार भी अपनी एक इंच जमीन न छोड़ने के संकल्प पर डटे हैं।

अवधनामा : बादशाहों को खूब 'बनाते' थे मौका-परस्त दरबारी

कृष्ण प्रताप सिंह

अवध के नवाबों को सनक के किस्से आज भी रस लेकर कहे व सुने जाते हैं, लेकिन यह जानना कहीं ज्यादा दिलचस्प है कि मतलब-परस्त दरबारी उनके 'नगाब' से 'बादशाह' बन जाने के बाद भी उनकी सनक के सही गलत फायदे उठाने के लिए कैसे-कैसे फरेब रचा करते थे। आठ जुलाई, 1837 को मोहम्मद अली शाह बादशाह बने तो उन्हें हासिल हुए भाति-भाति के ढेर सारे नजरानों में एक विलायती कुत्ता भी था। उसका डील-डौल देखकर वे इतने खुश हुए कि उसकी चौबीसों घंटे देखभाल के लिए दो नौकर तो नियुक्त किए ही, उसे गिजा खिलाने के लिए खजाने से एक रुपया रोज देने का हुक्म भी दे डाला। गौरतलब है कि उस दौर में एक रुपये में एक आदमी पखवारे भर दोनों जून भरपेट भोजन कर सकता था। लेकिन कुत्ता तो कुत्ता, उसकी वक्त बेवक्त की भौ-भौ ने जल्दी ही बादशाह को खिंखाकर रख दिया। दरअसल, रात को जैसे ही बादशाह नींद के आगोश में जाने को होते, कुत्ते को अपना चौकसी का फर्ज याद आ जाता। फिर तो वह हर आहट पर भौंकता और बादशाह की नींद हराम करता रहता। बेचारे कई दिन उन्हें रह गए तो उक्त दोनों नौकरों को बुलाकर कुत्ते की बेहूदगी पर खासी नाराजगी जताई और हर

हाल में उसे रोकने को कहा। यह भी पूछा कि कहीं उसका पेट भरने देते लिए एक रुपये की रकम कम तो नहीं पड़ जाती और वह भूख के मारे तो नहीं भौकता? एक चालाक दरबारी ने उनकी बात फौरन लपक ली और सुझाव दिया कि कुत्ते को रोज एक सेर गुलकंद और एक बोतल गुलाबजल खिला-पिलाकर रखा जाये तो उसका भौकना कम भले न हो, सुरील जरूर हो जाएगा। गुलकंद और गुलाबजल के असर से धीरे-धीरे उसके गला मीठा हो जाएगा। बादशाह ने फौरन उसके सुझाव पर अमल कर फरमान सुना दिया। फिर क्या था, गुलकंद व गुलाबजल हजम करने देते लिए दरबारी खुद कुत्ता बन बैठा। हा, रात जैसे ही बादशाह आरामगाह में जाते, नौकरों से कहकर कुत्ते को कहीं दूर बंधवा देता और अलस्सुबह फिर डूयौढ़ी पर ला खड़ा करवता।

की फरियाद आपके कानों तक पहुंचाने का बस यही एक तरीका है।' दूसरा दरबारी उसका भी बाप था। उसने फौरन सियारों में कंबल बंटवाने की तजवीज पेश कर दी। कह दिया, 'इससे सियारों का भला तो होगा ही, बादशाह को सवाब भी मिलेगा।' फिर बताया कि सियारों की कुल संख्या पांच सौ के आसपास ही होगी।

बादशाह ने फौरन पांच सौ कंबलों की कीमत उसके हवाले करा दी। लेकिन सियारों को कंबल भला कैसे बंटते? वे पहले की ही तरह गजर-दम मचाते रहे। इससे नाराज बादशाह ने उस दरबारी को तलब किया और पूछा, 'ये नामुराद कंबल पाने के बावजूद क्यामत क्यों बरपा किए हुए हैं? उन्हें जवाब मिला, 'हृजूर, उन बदनसीरों में किसी और बादशाह ने कभी कंबल नहीं बंटवाए। इसलिए अब वे खुश होकर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी इस दरियादिली की खबर सारे जहान को हो जाए।' हाँ, इससे भी मजे की बात यह कि जिस विलायती कृते को रोज एक सेर गुलकंद और एक बोतल गुलाब जल 'खिलाय-पिलाय' जाता था, 1840 में उसके मर जाने के दो साल बाद तक शाही खजाने से उसके नाम पर दो नौकरों की तनखाहें और रोजाना एक रुपया, एक सेर गुलकंद व एक बोतल गुलाब जल दिया जाता रहा। मोहम्मद अली शाह के बेटे अमजद अली शाह की बादशाहत के वक्त भेद खुला तो यह सिलसिला बंद हुआ।

सावधान! वे तंबाकू की
तरफ खींच रहे हैं बच्चों को

प्रियांक कानूनगे

वोट ही बेंगा।
 इसी तरह साल की शुरुआत में गोवा और उत्तराखण्ड में भी यही सवाल उठेगा। गोवा में आम आदमी पार्टी और टीएमसी पूरी ताकत के साथ उत्तर रही है। वहां दोनों दल बीजेपी सरकार के सामने कांग्रेस के साथ खुद को विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं उत्तराखण्ड में आम आदमी पार्टी मैदान में उत्तर चुकी है। पंजाब में भी सत्तारूढ़ कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी, अकाली दल और बीजेपी मैदान में हैं। मणिपुर में भी एक साथ कई दल चुनावी मैदान में हैं। हाल के सालों में अधिकतर चुनावों में दो पक्षों के बीच सीधी टक्कर ही देखने को मिली है। लेकिन इस बार जिस तरह इन सभी राज्यों में कई कोण अभी से दिख रहे हैं, यह देश की राजनीति में उस पुराने दौर की वापसी की आहट दे रहा है जब सियासी मैदान में कई खिलाड़ी होते थे। लेकिन क्या कई दलों के मैदान में उत्तरने से बहुकोणीय चुनाव हो जाएगा या मौजूदा ट्रैंड की तरह अंत में वोटर पक्ष और विपक्ष के लिए सिर्फ एक-एक विकल्प को चुनेगा? इसका जवाब तो चुनाव में ही मिलेगा। इसी से सभी दलों के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने की खाबिश का विस्तार होगा या नहीं, इसका भी पता चलेगा। बहुकोणीय चुनाव से वोट बंटने का असर क्या होता है, उस बारे में तो अगले साल चुनाव के नीति ही कुछ बता पाएंगे। लेकिन अब तक का ट्रैंड यही है कि इसका लाभ हाल के सालों में बीजेपी को मिला है। इसके पीछे कारण रहा है कि अधिकतर क्षेत्रीय दल चाहे तेलंगाना में हो या आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में हो या महाराष्ट्र में, वे सारे कांग्रेस के पतन की कीमत पर ही उभरे हैं। जिन-जिन राज्यों में कांग्रेस कमज़ोर होती गई वहां-वहां क्षेत्रीय दल उभरते गए। यह ट्रैंड पिछले तीन दशकों से है। सबसे नया उदाहरण दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली द्वारा या झारखण्ड जैसे राज्य वहां कांग्रेस से जो तोट बैंक निकला, उस पर ही अपनी पकड़ बनाकर क्षेत्रीय दल स्थापित हुए अधिकतर क्षेत्रीय दलों को वोट बेस कांग्रेस से ही मिलता रहा है। ऐसे में चूंकि क्षेत्रीय दल और कांग्रेस एक ही पिच पर खेलते रहे हैं तो ये एक ही वोट वर्ग में साझा करते हैं और बीजेपी का वोट बैंक इससे प्रभावित नहीं होता है। यह चुनाव दर चुनाव दिखा भी है। लेकिन जानकारों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में हालात बदले भी हैं। अब इन सभी के लिए बीजेपी राज्य लड़ना प्राथमिक सियासी चुनौती बन गई। लगभग एक दशक से देश की राजनीति के केंद्र में आ चुकी बीजेपी इन क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ा खतरा बन गई। इसके अलावा बीजेपी की तरह कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल इनका भी अपना वोट बैंक बन गया।

ऐसे में अब बहुकोणीय चुनाव का असर किसके वोट बैंक पर पड़ेगा उसका आकलन गलत भी साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश की हैरानी मिसाल लें, तो यहां अगर कांग्रेस उभर कर अपना वोट बैंक बढ़ाती है तब वह बीजेपी में सेंध लगाएगी या विपक्ष में, यह अभी कहना जल्दबाज़ होगा। एसपी के नेता ने कहा कि पारंपरिक रूप से बीजेपी का वोट कांग्रेस की ओर जा सकता है, जो एसपी की ओर कभी नहीं आएगा। यही बात दूसरे राज्यों में भी लागू होती है। जाहिर है, सभी दल बहुकोणीय चुनाव में अपने लिए लाभ का आकलन अधिक करेंगे, लेकिन इसके लिए ठोस आधार नहीं हैं। इसी तरह ओवैसी की पार्टी के बारे में कहा गया है कि उनकी पार्टी मुस्लिम वोट बांटती है। लेकिन अब तक इसके कोई स्पष्ट सियासी प्रमाण नहीं मिले हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सामने कांग्रेस-लेफ्ट का गठबंधन था, जो वहां की स्थापित पारिच्यां है। उनके साथ इंडियन सेक्युलर फ्रंट की पार्टी भी थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो यही बात देखी गई कि मुस्लिम मतों का बंटवारा नहीं होता।

प्रियांक कानूनगो

जाहिर है, हमारे बच्चे बहुत तेजी से तंबाकू के खतरे के शिकार हो रहे हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इस समस्या को रोकने के प्रयासों को तेज करना होगा। हमारा मानना है कि अगर कॉटपा (सिगरेट ऐंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट- 2003) कड़े नियमों और दंडों से लैस हो, तो यह तंबाकू इस्तेमाल को रोकने में महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। चिंता की बात यह है कि तंबाकू लौबी लंबे समय से इन कानूनों को दरकिनार कर लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। तंबाकू कंपनियों के लिए अपने उत्पादों पर 'तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' जैसी वैधानिक चेतावनियों को प्रमुखता से शामिल करना आवश्यक है। लेकिन इन्होंने केसर, इलायची, गुलाब और ऐसी ही अन्य सामग्रियों की आड़ ले ली है और अपने उत्पादों का विज्ञापन कर इन कानूनों को दरकिनार कर दिया है। बहुत सारी तंबाकू कंपनियां बच्चों को तंबाकू उत्पादों के प्रति आकर्षित करने के लिए फिल्म अभिनेताओं से विज्ञापन कराती हैं। कायदे से तो ऐसे विज्ञापनों को दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए। यहां इस बात का उल्लेख है कि तंबाकू निरोधी विभिन्न कानूनों में निर्धारित जुर्माने बहुत कम हैं। इन कानूनों के जरिए तंबाकू इस्तेमाल को रोकना संभव नहीं है। कल्पना कीजिए, किसी बच्चे को तंबाकू सेवन में धकेलने जितने बड़े अपराध के लिए सिर्फ 200 रुपये जुर्माना! इस पुराने पड़ चुके नियम में भी बदलाव लाना होगा, ताकि बच्चे निडर होकर किसी वैकल्पिक रास्ते की तलाश न कर सकें। एनसीपीसीआर ने भी कॉटपा के साथ मिल कर स्कूल स्तर पर पहल की है। अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एनसीपीसीआर स्कूलों में कैमरे भी लगा रहा है।

देश/विदेश संदेश

वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 101वें नंबर पर फिसला भारत, बांग्लादेश और पाक भी हैं आगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। वैश्विक भुखमरी सूचकांक (उप) 2021 ने भारत को 116 देशों में 101वां स्थान दिया है। 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। 2021 की रैंकिंग के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल ने भारत से बहतर प्रदर्शन किया है। सहायता कार्यों से जुड़ी आयरलैंड की एजेंसी का क्षर्ण वर्क्फाइंड और जर्मनी का संगठन वेट हॉप हिक की ओर से सुनुक्त रूप से तैयारी की गई रिपोर्ट में भारत में भूख के स्तर को चिंताजनक बताया गया है। भारत का जीएचआई स्कोर भी पिछे गया है। यह साल 2000 में 38.8 था, जो 2012 और 2021 के बीच 28.8-

27.5 के बीच रहा। जीएचआई स्कोर की गणना चार पैरामीटर पर

2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। अब 116 देशों में



की जाती है, जिनमें अत्यधिक, कुपोषण, बच्चों की वृद्धि दर और बाल मृत्यु दर शामिल हैं। साल

यह 101वें स्थान पर आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पड़ासी देश जैसे नेपाल (76), बांग्लादेश (76),

म्यांगांग (71) और पाकिस्तान (92) भी भुखमरी को लेकर चिंताजनक स्थिति में हैं। लेकिन भारत की तुलना में ये सभी अपने नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराने को लेकर बहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोविड-19 और महामारी संबंधी प्रतिवेदी की वजह से लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जहां दुनिया भर में बच्चों की वैस्टिंग की दर सबसे ज्यादा है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में चाइल्ड वैस्टिंग की दर 1998 और 2002 वें बीच 17.1 प्रतिशत से बढ़कर 2016 और 2020 के बीच 17.3 प्रतिशत हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है असर्मध्य होगा।

कि भारत ने अन्य पैरामीटरों में सुधार दिखाया है जैसे कि बाल मृत्यु दर, बाल स्ट्रिंग की व्यापकता और अपर्याप्त भोजन के कारण अत्यधिक व्यापकता। रिपोर्ट में चीन, बांग्लादेश और गुरुवार को मामले के सिलसिले में ठांगे शहर के बर्तक नगर पुलिस थाने में पेश हुए। धिकारी ने कहा कि उनका बायान दर्ज किया गया और उन्हें एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जिन्होंने मंत्री को 10,000 रुपए के मुरब्बे और एक जमानत पर रिहा कर दिया। शिकायतकर्ता आनंद करमुसे ने आरोप लगाया था कि उन्हें आब्दान के बंगले में ले जाया गया और मंत्री की मौजूदगी में एक

अपहरण और मारपीट के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आब्दान गिरफ्तार, जमानत पर छुटे

ठाणे (एजेंसी)। महाराष्ट्र के आवास मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता जितेंद्र आब्दान को अपने घर पर एक व्यक्ति पर कथित रूप से हमला करने के मामले में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हाफ़ाज़ा तहत सहित अठारह देशों ने पांच से पांच के काम के जीएचआई स्कोर के साथ टॉप स्थान साझा किया है। जीएचआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी दुनिया के लिए भूख से खिलाफ लड़ाई खतरनाक तरीके से पटरी और वर्तमान अनुमानों के आधार पर, दुनिया और विशेष रूप से 47 देश 2030 तक निम्न स्तर की भूख को प्राप्त करने में एक



सोशल मीडिया पोस्ट के लेकर पीटा शाम को उनसे मिलने आए और उनसे कहा कि उन्हें पुलिस थाने को उत्तित जाकर करने और आवश्यक उन्हें आब्दान, लेकिन इसके बंगले में ले गए। करमुसे ने आरोप लगाया था कि मंत्री की उस तस्वीर को लेकर, जिसे उन्होंने फेसबुक पर साझा किया था कि उन्हें आरोप लगाया था कि उन्हें आब्दान के बंगले में ले जाया गया और मंत्री की मौजूदगी में एक

सिविल इंजीनियर, करमुसे ने आरोप लगाया था कि उन्हें उन्हें एक पुलिसकर्मी पांच अप्रैल, 2020 की

लगातार बिहारी जम्मू-कश्मीर की स्थिति... बीजेपी नेता ने की एक्शन की मांग

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भजपा) के वरिष्ठ नेता कविदेव गुना ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में रिंजेंट लागार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, ठज्म्मू-कश्मीर में हालात लागात लिंगटन जारी है। एसएलएस मार्ग पर एक जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, ठज्म्मू-कश्मीर में हालात लागात लिंगटन जारी है। एसएलएस ने गांवों के बाजारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाही थी। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आधिकारिक गाड़ी की भी सुरक्षा के लिए जारी है। विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया गया है। जब जम्मू-कश्मीर के अधिकारी ने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया तो उन्होंने एक विपुल घटना के बाद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लिया। उन्होंने कहा कि उनकी आ